आई क्यू सिटी फाउंडेशन और अन्य

बनाम

भारत संघ और अन्य

[2017 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 502]

1 अगस्त, 2017

[दीपक मिश्रा, अमिताव रॉय और ए.एम. खानविलकर, जेजे.]

शिक्षा/शैक्षणिक संस्थानः मेडिकल कॉलेज-शैक्षणिक वर्ष के लिए एमबीबीएस पाठ्यक्रम के अपने 5 वें बैच के लिए अनुमति के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया 2017-18 - मूल्यांकनकर्ताओं ने संस्थान के निरीक्षण के बाद कुछ कमियों को पाया भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) ने एस.यू. एम.एम.ए. के मूल्यांकन पर विचार करने के बाद केंद्र सरकार को अनुमति का नवीनीकरण नहीं करने के लिए रिपोर्ट की सिफारिश की गई-हालाँकि, केंद्रीय सुनवाई समिति सरकार का मानना था कि कमियों की प्रकृति ऐसी नहीं थी कि उन्हें अस्वीकार किया जाए-केंद्र सरकार ने इसे स्वीकार करने के बजाय अंतिम निर्णय ने सुनवाई समिति की सिफारिश के आलोक में मामले को समीक्षा के लिए एमसीआई को वापस भेज दिया-एमसीआई ने अनुपालन सत्यापन मूल्यांकन करने के लिए एक टीम का गठन किया-टीम ने अपने दायरे को सीमित करने के बजाय एक नियमित निरीक्षण किया सुनवाई समिति की टिप्पणियों के अनुपालन की समीक्षा करना-टीम ने अपने अनुपालन में कुछ कमियों को नोट किया सत्यापन-एमसीआई ने फिर से अस्वीकृति की सिफारिश की-केंद्रीय सरकार ने दिनांक 31 के विवादित आदेश द्वारा नवीनीकरण की अनुमति की योजना को खारिज कर दिया-याचिकाकर्ता-कॉलेज ने चुनौती दी आदेश अंतर्गत अनुच्छेद 32 संविधान का-अभिनिर्धारित- धारा 10 - चिकित्सा परिषद अधिनियम और उसके तहत बनाए गए

विनियम और नियम, एमसीआई की शक्ति को को देखते हुए एक पूर्ण सिद्धांत के रूप में निर्धारित करके प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है कि यदि मामले को केंद्र सरकार द्वारा अनुपालन सत्यापन के लिए वापस भेजा जाता है, तो मूल्यांकनकर्ता का निरीक्षण केवल उल्लिखित वस्तुओं के सत्यापन तक सीमित है और वे अन्य बातों को नहीं समझ सकते हैं। कमियाँ। अनुपालन सत्यापन के लिए केंद्र सरकार के निर्देश को सीमित रिमांड के रूप में नहीं माना जाना चाहिए-केंद्र सरकार का आदेश तर्कसंगत नहीं था-यह अनिवार्य था अपनी ओर से कारण बताने के लिए-केंद्र सरकार को याचिकाकर्ता-कॉलेज-को सुनवाई का और अवसर देने का निर्देश दिया गया है।

चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956- धारा 10 - ए.

न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश जारी करते हुए, अभिनिर्धारित किया-

1. चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 10-ए को पढ़ने पर, नियम और उनके तहत बनाए गए विनियम, एक पूर्ण सिद्धांत के रूप में यह निर्धारित करके एमसीआई की शक्ति को प्रतिबंधित करना अनुचित होगा कि एक बार जब केंद्र सरकार अनुपालन सत्यापन के लिए मामले को एमसीआई को वापस भेज देती है और मूल्यांकनकर्ता कॉलेज का दौरा करते हैं तो वे केवल उल्लिखित वस्तुओं का सत्यापन करेंगे और नेल्सन की नजर डालेंगे, भले ही वे कुछ अन्य कमियों को समझते हों। केंद्र की दिशा अनुपालन सत्यापन रिपोर्ट के लिए सरकार को एक सीमित रिमांड के रूप में नहीं माना जाना चाहिए जैसा कि इसके भीतर समझा जाता है सिविल प्रक्रिया संहिता या किसी अन्य कानून का ढांचा। खुले रिमांड और सीमित रिमांड के सिद्धांतों के बीच का अंतर रिमांड, आकर्षित नहीं है। [पैरा 29] [322-डी-एफ]

2. वास्तविक अनुपालन करने वाली संस्थाओं को हमेशा डेमोक्लिस की तलवार के नीचे नहीं रखा जाना चाहिए। स्थिरता लाई जा सकती है केंद्र सरकार द्वारा निभाई

गई सकारात्मक भूमिका। और यह व्यक्त करते समय एक दृष्टिकोण और कारणों की अनुपस्थिति का उल्लेख किया जाता है निर्णय संवेदनशील रूप से अतिसंवेदनशील। [पैरा 29] [322-जी]

3. याचिकाकर्ता तब से कॉलेज चला रहे हैं। 2013-14 जो छात्र अपनी शिक्षा जारी रख रहे हैं, वे 2017-18 के लिए जारी रखेंगे। केंद्र सरकार का आदेश है - कोई तर्क नहीं। अपनी ओर से कारण बताना अनिवार्य है। उक्त उद्देश्य के लिए, केंद्र सरकार एक और खर्च वहन करेगी याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का अवसर और नवगठित निरीक्षण समिति की सहायता। [पैरा 30] [322 - एच; 323-ए-बी]

मनोहर लाल शर्मा बनाम भारतीय चिकित्सा परिषद और अन्य (2013) 10 एससीसी 60: [2013] 9 एससीआर 325; रॉयल मेडिकल ट्रस्ट (पंजीकृत) और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (2015) 10 एस. सी. सी. 19-पर भरोसा किया।

डॉ. आशीष रंजन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (2016) 11 एस. सी. सी. 225; भारतीय चिकित्सा परिषद बनाम कलिंग आयुर्विज्ञान संस्थान (के. आई. एम. एस.) और अन्य (2016) 11 एससीसी 530: [2016] 4 एस. सी. आर. 403-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2016] 11 एससीसी 225	संदर्भित किया गया है	पैरा 7
[2013] 9 एससीआर 325	उस पर भरोसा करें	पैरा 19
[2016] 4 एससीआर 403	संदर्भित किया गया है	पैरा 21
[2015] 10 एससीसी 19	उस पर भरोसा करें	पैरा 28

सिविल मूल न्यायनिर्णयः लिखित याचिका (सिविल) संख्या 502/2017

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत।

सलमान खुर्शीद, एस. जी. हसनैन, गुरुकृष्ण कुमार, ए. शरण, पी. एस. पटवालिया, कपिल सिब्बल, वी. गिरि, निधेश गुप्ता, आर. बसंत, अमित सागर, सुश्री बीना माधवन, सुश्री आकांक्षा मेहरा (मेसर्स के लिए)। वकील एस. निट एंड कंपनी), रंजन कुमार पांडे, के. पी. गौतम, संदीप बिष्ट, अंशुमान बी., श्रेय वर्धन, रंजीता रोहतगी, गिरिजापति कौशल, मृत्युंजय कुमार सिन्हा, कुणाल वजानी, प्रणय गोयल, निखिल रंजन, चिरंजीवी शर्मा, अबीरथ ठाकुर, साकेत सीकरी, विकास मुद्गल, गोपाल शंकरनारायणन, वी. श्यामोहन, सूर्य प्रकाश, एहसान जावेद, पंकज पांडे, अमितेश कुमार, शशांक एस. सिंह, सुश्री बबीता कुशवाहा, सुश्री प्रीति कुमारी, एम. के. सिन्हा, अधिवक्ता याचिकाकर्ताओं के लिए।

मनिंदर सिंह, एएसजी, विकास सिंह, अजीत कुमार सिन्हा, सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा, वरिष्ठ अधिवक्ता, गौरव शर्मा, सुश्री अमनदीप कौर, प्रतीक भाटिया, धवल मोहन, सुश्री वारा गौर, सुश्री वृति जिंदल, आर. बालासुब्रमण्यम, प्रभास बजाज, अक्षय अमृतांशु, संजय कुमार पाठक, जोहेब हुसैन, सुश्री बीनू टम्टा, दीपक गोयल, आर. के. राठौर, विभु शंकर मिश्रा, जी. एस. मक्कर, मिश्रा सौरभ, टी. सिंह देव, अंकित लाल, अरुण बत्रा, तनुज बग्गा, अधिवक्ता उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय दीपक मिश्रा, जे. द्वारा सुनाया गया था।

आई. क्यु सिटी ने इस रिट याचिका में कहा है कि भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 10-ए के तहत पारित (संक्षिप्तता के लिए "अधिनियम") सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, इसमें पहले प्रतिवादी द्वारा, और आगे याचिकाकर्ता कॉलेज को चौथे नवीनीकरण के लिए अनुमति देने के लिए उक्त प्रतिवादी को 5वें बैच (150 छात्र) एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश की सुविधा के लिए शैक्षणिक वर्ष 2017-2018 के लिए निर्देश जारी करें।

2. विवाद के निर्णय के लिए आवश्यक तथ्यों का खुलासा यह है कि शिक्षण अस्पताल से जुड़े आई. क्यू. सिटी मेडिकल कॉलेज, अर्थात् आई. क्यू. सिटी नारायण मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना उसी वर्ष की गई थी। 2013 याचिकाकर्ताओं द्वारा 150 (एक सौ पचास) के अंतर्ग्रहण के साथ एमबीबीएस पाठ्यक्रम में सीटें। भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) ने आयोजित किया पश्चिम बंगाल के बर्दवान में 150 छात्रों के वार्षिक प्रवेश के साथ नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए 15.07.2013 पर एक निरीक्षण और अनुमति पत्र (L. O. P.) प्रदान किया गया। शैक्षणिक वर्ष 2013-14। दूसरे (पहले नवीनीकरण), तीसरे (दूसरे) के लिए अनुमति के नवीनीकरण के लिए 04.07.2014,10.06.2015 और 15.12.2015 दिनांकित पत्रों के माध्यम से याचिकाकर्ता पर एमबीबीएस छात्रों के नवीनीकरण) और चौथे (तीसरे नवीनीकरण) बैच शैक्षणिक वर्षों के लिए कॉलेज क्रमशः 2014-15,2015-16 और 2016-17 प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा प्रदान किए गए थे। 06.07.2016 पर, याचिकाकर्ता-कॉलेज ने शैक्षणिक वर्ष के चौथे नवीनीकरण के लिए आवश्यक शुल्क के साथ अपनी योजना प्रस्तुत की जो एमबीबीएस पाठ्यक्रम में 150 छात्रों के 5वें बैच के प्रवेश से संबंधित है। 09.07.2016 पर, दूसरा प्रत्यर्थी ने कॉलेज को सूचित किया कि शैक्षणिक वर्ष 2017-18 के लिए अनुमति के नवीनीकरण के लिए मूल्यांकन द्वारा किया जाएगा 15.07.2016 के बाद किसी भी समय इसके द्वारा नियुक्त मूल्यांकनकर्ताओं और याचिकाकर्ताओं को मानक निरीक्षण प्रपत्र ए, प्रपत्र बी और शैक्षणिक वर्ष के लिए घोषणा प्रपत्र 2017-18 और उन्हें तैयार रखें प्रपत्र ए, प्रपत्र बी और घोषणा प्रपत्र की सॉफ्ट प्रतियों वाली एक कॉम्पैक्ट डिस्क विधिवत प्रस्तुत की और आवश्यक दस्तावेजों की प्राप्ति पर, दूसरे प्रतिवादी ने मूल्यांकनकर्ताओं की एक टीम का गठन किया और उन्हें निर्देश दिया कि महाविद्यालय का मूल्यांकन निरीक्षण करना। निरीक्षण दल अर्थात्, मूल्यांकनकर्ताओं ने कॉलेज का औचक निरीक्षण किया 03.11.2016 और

04.11.2016। मूल्यांकनकर्ताओं ने आई. क्यू. सिटी फाउंडेशन और अन्य की कुछ कमियों की ओर इशारा किया। महाविद्यालय को सूचित किया और दिनांकित 04.11.2016 मूल्यांकन रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया। नियमित निरीक्षण रिपोर्ट में यह कहा गया है कि शिक्षण संकाय और रेजिडेंट डॉक्टरों में कमी क्रमशः केवल 4.5% और 3.50% थी जो निर्धारित सीमा के भीतर थी। दो अन्य कमियां जिन्हें इंगित किया गया था, जैसा कि दावा किया गया था, पूरी तरह से थीं उपचार योग्य और कॉलेज द्वारा विधिवत सुधार किया गया था। 22.12.2016 पर प्रत्यर्थी संख्या 2 की कार्यकारी समिति ने मूल्यांकन पर विचार किया निर्धारकों की रिपोर्ट और प्रत्यर्थी को सिफारिश करने का निर्णय लिया नहीं। मैं शैक्षणिक वर्ष 2017-18 के लिए चौथे नवीनीकरण के लिए कॉलेज की अनुमति का नवीनीकरण नहीं करूँगा।

3. जैसा कि आगे बताया गया है, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपने दिनांकित 03.02.2017 पत्र द्वारा कॉलेज को दिनांकित सिफारिश के बारे में सूचित किया। 28.01.2017 अनुमति को अस्वीकार करने के लिए प्रतिवादी संख्या 2 का शैक्षणिक वर्ष 2017-18 के लिए चौथे नवीकरण के लिए महाविद्यालय ने महाविद्यालय से दस्तावेजी साक्ष्य के साथ एक विस्तृत बिंदु-वार अनुपालन प्रस्तुत करने का आहवान किया। महाविद्यालय को आगे इस बारे में सूचित किया गया कि सुनवाई समिति के समक्ष 09.02.2017 पर होने वाली सुनवाई। कॉलेज के प्रतिनिधियों की एक टीम निर्धारित तिथि पर सुनवाई समिति के समक्ष पेश हुई और कॉलेज की अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्रत्यर्थी संख्या 2 के मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा की गई टिप्पणियां और टिप्पणियां। मार्च, 2017 के दूसरे सप्ताह में, याचिकाकर्ताओं को प्रथम प्रतिवादी द्वारा जारी किए गए 01.03.2017 दिनांकित आदेश की एक प्रति प्राप्त हुई, जिसमें दर्ज किया गया था सुनवाई समिति द्वारा पारित सिफारिशें/आदेश अधिनियम की धारा 10-ए (4) के तहत प्रतिवादी संख्या 1। सुनवाई समिति की सिफारिश इस आशय की थी कि दूसरे प्रतिवादी

द्वारा बताई गई कमियां ऐसी नहीं थीं जो उस पर अस्वीकृति का कारण बन सकें। स्टेज। सुनवाई समिति के उपरोक्त निष्कर्षों के बावजूद, प्रथम प्रतिवादी ने अंतिम निर्णय लेने के बजाय मामले को वापस भेज दिया प्रतिवादी संख्या 2 को याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के साथ सुनवाई समिति की सिफारिशों/निष्कर्षों के आलोक में इसकी समीक्षा करने और अपनी सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए।

4. उक्त पत्राचार की प्राप्ति पर, दूसरा प्रतिवादी 17.03.2017 महाविद्यालय के अनुपालन सत्यापन मूल्यांकन के लिए एक दल का गठन किया गया। आकलनकर्ताओं की टीम ने अनुपालन सत्यापन करने के बजाय, 21.03.2017 पर एक नियमित परीक्षण किया। यादृच्छिक तरीके से निरीक्षण और सुनवाई की टिप्पणियों/टिप्पणियों के अनुपालन की समीक्षा करने के उनके दायरे तक सीमित करने के बजाय समिति एक अलग तरह का मूल्यांकन करने के लिए आगे बढ़ी।

5. यह तर्क दिया जाता है कि हालांकि अनुपालन निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था, मूल्यांकनकर्ताओं ने कॉलेज को एक प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी प्रतिनिधित्व और तदनुसार, कॉलेज ने आवश्यक प्रस्तुत किया प्रत्यर्थी संख्या 2 को प्रतिनिधित्व। याचिकाकर्ताओं के रुख के अनुसार, मूल्यांकनकर्ताओं ने अपने अनुपालन में कुछ कमियों को नोट किया सत्यापन। प्रत्यर्थी संख्या 2 की कार्यकारी समिति ने अपनी 28.04.2017 पर बैठक लेकिन बैठक के कार्यवृत्त अपलोड नहीं किए गए थे उत्तरदाता संख्या 2 की आधिकारिक वेबसाइट 29.05.2017 तक और थी याचिकाकर्ताओं को सूचित नहीं किया गया।

6. याचिकाकर्ताओं का यह रुख है कि 20.05.2017 पर, याचिकाकर्ताओं ने [1s प्रतिवादी से संपर्क किया और एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत किया उस दिन अनुपालन सत्यापन और पाई गई कमियों के संबंध में चौथे नवीनीकरण (पांचवें बैच के 150 छात्रों

के प्रवेश) के लिए एमबीबीएस शैक्षणिक वर्ष के लिए पाठ्यक्रम 2017-18। यह आरोप है कि आदेश दिनांकित है 31.05.2017 कॉलेज को 30.06.2017 पर सूचित किया गया था। अवैध रूप से अस्वीकार किया जाना सही नहीं है क्योंकि इसमें भारी कमियां हैं। एमसीआई का यह रुख है कि "खुली रिमांड" और "सीमित रिमांड" का सवाल है। रिमांड "उत्पन्न नहीं होता है। एक बार मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा निरीक्षण किए जाने के बाद, इसे पूरी तरह से और उचित रूप से किया जाना चाहिए ताकि चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान का मानक बनाए रखा जा सके और कहा गया मानक गैर-परिवर्तनीय है। मूल्यांकनकर्ताओं की रिपोर्ट में जिस स्थिति का उल्लेख किया गया है 21.03.2017 उन्होंने कहा कि कुछ कमियां जिनका दिनांक 1 की पिछली मूल्यांकन रिपोर्ट में उल्लेख नहीं किया गया था, वे न तो स्वीकार्य हैं और न ही मान्य हैं, क्योंकि यह सुनिश्चित करना मूल्यांकनकर्ताओं का गंभीर कर्तव्य है कि मेडिकल कॉलेज में कोई कमी न हो और वे कमियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं और इसलिए, यह दलील कि यह जनादेश को पार कर गई है, न केवल अपरिवर्तनीय है, बल्कि पूरी तरह से अकल्पनीय है।1 (2016) II एस. सी. सी. 225

8. हमने श्री मुकल रोहतगी को सुना है, जिनके लिए विद्वान वरिष्ठ वकील हैं याचिकाकर्ता, श्री मनिंदर सिंह, भारत संघ के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल और श्री विकास सिंह, के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील एमसीआई।

9. यह श्री रोहतगी, विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया है याचिकाकर्ताओं ने कहा कि 1s प्रतिवादी मामले को एमसीआई को वापस नहीं भेज सकता था क्योंकि अंतिम निर्णय लेना उसकी ओर से अनिवार्य था और इसके अलावा, इसे कार्यकारी समिति की राय से सहमत नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मूल्यांकनकर्ताओं ने रिमांड के आदेश का उल्लंघन किया था। कि इसके अलावा, श्री रोहतगी प्रस्तुत करते हैं, निर्णय लेने का कोई औचित्य नहीं था अंतिम तिथि पर, अर्थात 31.05.2017।

10. श्री सिंह, एमसीआई की ओर से पेश वरिष्ठ वकील, अधिनियम की धारा 10-ए का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि किसी संस्थान को शिक्षा प्रदान करने में निरंतरता बनाए रखनी होती है और जहां अनुपालन सत्यापन के दौरान प्रमुख कमियां स्पष्ट रूप से स्पष्ट होती हैं, कोई संस्थान ऐसा नहीं कर सकता है। पहले की मूल्यांकन रिपोर्ट पर भरोसा करने की अनुमति दी जाए। श्री सिंह के अनुसार, संस्थान को हमेशा अनुपालन करना पड़ता है और यह किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता है। दोलन स्थिति। उनके अनुसार, एक दिन इसमें संकाय सदस्य हो सकते हैं और कानून के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहें और एक और दिन खेल की पूरी तरह से अवहेलना करें प्रावधान के अनुसार, ऐसी स्थिति के लिए चिकित्सा शिक्षा की पवित्रता को सूली पर चढ़ाया जाएगा।

11. तथ्यात्मक मैट्रिक्स का पूरा प्रक्षेपण करने के लिए, हम सोचते हैं अभिलिखित कार्यकारी समिति की राय को संदर्भित करना आवश्यक है नियमित सत्यापन पर 22.12.2016 पर। उक्त रिपोर्ट इस प्रकार है - निम्नलिखित हैः" 46. पांचवें बैच (150) के लिए एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए अनुमति का नवीनीकरण छात्र) आई. क्यू. सिटी मेडिकल कॉलेज, बर्दवान, पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कोलकाता यू/एस 10ए शैक्षणिक वर्ष के लिए आई. एम. सी. अधिनियम, 1956 2017-18।

पढ़िएः एमबीबीएस के लिए अनुमति के नवीनीकरण के संबंध में मामला आई. क्यू. सिटी मेडिकल कॉलेज के 5वें बैच (150 सीटें) के लिए पाठ्यक्रम, पश्चिम बंगाल के अंतर्गत बर्दवान,पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कोलकाता आई. एम. सी. अधिनियम की धारा 10ए के तहत, 1956 शैक्षणिक वर्ष 2017-18 के लिए।

परिषद की कार्यकारी समिति ने विचार किया कि मूल्यांकन रिपोर्ट (3 और 4 नवंबर, 2016) और नोट किया गया निम्नलिखितः

1. हालांकि भर्ती होने वाले रोगियों की संख्या बिस्तर के बराबर थी 80 प्रतिशत का अधिभोग लेकिन वास्तविक सत्यापन पर अधिकांश प्रवेश थेताजा और नया पाया गया।

2. केंद्रीय पुस्तकालयः यह वातानुकूलित नहीं है। पढ़ने के लिए कमरा निवासी उपलब्ध नहीं हैं।

3. छात्रों का छात्रावासः लड़कों के छात्रावास में आगंतुक कक्ष ए. सी. पढ़ता है। कंप्यूटर और इंटरनेट के साथ कमरा, मनोरंजन कक्ष उपलब्ध नहीं हैं। लड़कियों में स्वच्छता बहुत खराब है।

4. निवासियों का छात्रावासः उपलब्ध आवास 48 के खिलाफ है 85 की आवश्यकता।

5. एनाटॉमी विभागः उपलब्ध घुड़सवार नमूने 45 हैं।

6. फार्माकोलॉजी विभागः 1 प्रदर्शन कक्ष में, वहाँ हैं मेज के साथ केवल 15 कुर्सियाँ।

7. आरएचटीसीः आवासीय आवास उपलब्ध नहीं है।

8. मूल्यांकन रिपोर्ट में बताई गई अन्य कमियां। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, परिषद की कार्यकारी समिति ने केंद्र सरकार को सिफारिश करने का निर्णय लिया। नवीनीकरण नहीं करना श्चिम बंगाल के अंतर्गत आई. क्यू. सिटी मेडिकल कॉलेज, बर्दवान में 150 एम. बी. बी. एस. छात्रों के पांचवें बैच के प्रवेश के लिए अनुमति पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कोलकाता के अंतर्गत आई. एम. सी. अधिनियम, 1956 की धारा 10ए के तहत शैक्षणिक वर्ष 2017-18 के लिए बंगाल।

12. कार्यकारी समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, प्रथम न्यायाधीश ने दिनांक 03.02.2017 के संचार के माध्यम से उसे संलग्न किया प्रतिवादी संख्या 2 के दिनांक 28.01.2017 ने कॉलेज को सूचित किया किः

> " विषयः शैक्षणिक सत्र के लिए 150 एमबीबीएस छात्रों के 5वें बैच के प्रवेश के लिए अनुमति का नवीनीकरण 2017-18-सुनवाई आई. एम. सी., 1956 की धारा 10ए (4) के तहत आवेदक को। सर/मैडम मुझे इसके साथ एम. सी. आई. के दिनांकित 28.01.2017 पत्र की एक प्रति अग्रेषित करने का निर्देश दिया गया है जिसमें शैक्षणिक सत्र 2017-18 के लिए आपके कॉलेज में नवीनीकरण अनुमति के संबंध में अस्वीकृति की सिफारिश की गई है।
>
> 2. आई. एम. सी. अधिनियम, 1956 की धारा 10ए (4) में निहित प्रावधानों के अनुसरण में, आपको इस पर सुनवाई करने का निर्णय लिया गया है। 09.02.2017 10 बजेः 30 इस आई. क्यू. सिटी फाउंडेशन और ए. एन. आर. द्वारा गठित समिति द्वारा। कमरा संख्या 243, ए-विंग, निर्माण में इस उद्देश्य के लिए मंत्रालय भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली।
>
> 3. आपसे अनुरोध है कि आप व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों या किसी अधिकृत व्यक्ति को प्रतिनियुक्त करें।आपके न्यास/समाज के मामले को प्रस्तुत करने के लिए प्रतिनिधि आवश्यक जानकारी के साथ एमसीआई का अस्वीकृति पत्र निर्दिष्ट तिथि और समय पर संलग्न प्रारूप में जो विफल हो जाता है इस योजना पर एकतरफा निर्णय लिया जाएगा। आपसे भी अनुरोध है कि जानकारी/सामग्री की

दो हार्ड प्रतियां और एक सॉफ्टकॉपी लाएं आप संलग्न प्रारूप में समिति के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रस्ताव करते हैं एमएस वर्ड में। आपसे पुष्टि पत्र भेजने का भी अनुरोध किया जाता है। ई-मेल द्वारा भागीदारी। “sujeet.charan@nic.in"।

13. उत्तरदाता द्वारा किए गए संचार के अनुसरण में,याचिकाकर्ता कॉलेज के प्रतिनिधियों की एक टीम के सामने पेश हुई 09.02.2017 पर सुनवाई समिति और स्पष्ट बिंदु-वार अनुपालन निर्धारकों द्वारा की गई टिप्पणियों/टिप्पणियों और प्रस्तुत किए गए उस संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य। मार्च के दूसरे सप्ताह में, 2017, जैसा कि पहले कहा गया है, याचिकाकर्ताओं को 01.03.2017 दिनांकित पत्र प्राप्त हुआ पारित सिफारिशों/आदेशों को दर्ज करते हुए प्रथम प्रतिवादी द्वारा जारी किया गया सुनवाई समिति की सिफारिशों को पुनः प्रस्तुत किया जाता है नीचेः

"आई. क्यू. सिटी मेडिकल कॉलेज, बुरवान पश्चिम बंगाल, [का नवीनीकरण] पाँचवें बैच की अनुमति (150) सीटें)]	संकाय की कोई कमी नहीं है, निवासी और नैदानिक सामग्री ।
	महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत फोटोग्राफिक साक्ष्य से पता चलता है कि केंद्रीय पुस्तकालय/छात्र छात्रावास, आवासीय छात्रावास/आर. एच. टी. सी. में वातानुकूलन से संबंधित कमियां हैं। आवास और नमूने को ठीक कर दिया गया है।

	कमियां ऐसी नहीं हैं जो कॉलेज के इस स्तर पर अस्वीकृति का कारण बन सकें।

14. यद्यपि सुनवाई समिति ने उपरोक्त अनुशंसा भेजी थी, फिर भी प्रथम प्रतिवादी ने इसे संदर्भित करना उचित समझा। वह एमसीआई के लिए वापस मायने रखता है और संदर्भ का तरीका इस प्रकार हैः

“4”	आई. क्यू. सिटी मेडिकल कॉलेज, बर्दवान, पश्चिम बंगाल	कोई कमी नहीं है संकाय, निवासी और नैदानिक सामग्री।
	महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अनुमति का नवीनीकरण 5 टीएच बैच (150 सीटें)	फोटोग्राफिक सबूत यह बताता है कि कमियां वातानुकूलन से संबंधित केंद्रीय पुस्तकालय/छात्र छात्रावास, निवासी छात्रावास / आरएचटीसी आवास और नमूने हैं ठीक किया गया। कमियां ऐसी नहीं हैं।
		इस पर अस्वीकृति देने के लिए महाविद्यालय का स्तर।

2. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, एमसीआई से उपरोक्त की समीक्षा करने का अनुरोध किया जाता है आवेदक महाविद्यालयों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के साथ सुनवाई समिति की सिफारिशों के आलोक में योजनाएं और तदनुसार इस मंत्रालय को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करें।

15. आवेदक महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अनुपालन मूल रूप में इसके साथ संलग्न हैं। कॉलेज जिसके लिए हमने प्रासंगिक उद्धरण को पुनः प्रस्तुत किया है।

16. अनुपालन सत्यापन के लिए गए मूल्यांकनकर्ताओं की टीम ने 21.03.2017 पर एक आकस्मिक सत्यापन किया और कुछ बातों का उल्लेख किया जिन निपुणताओं का हम बाद में उल्लेख करेंगे।

उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद प्रथम प्रतिवादी ने 31.05.2017 को एमसीआई की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और शैक्षणिक वर्ष 2017-2018 के लिए एलपीओ से इनकार कर दिया याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उक्त पत्र 21.06.2017 पर प्राप्त हुआ था। उस दिन पत्र मिला था या नहीं, यह नहीं हैप्रेजेंटी में प्रासंगिक। प्रासंगिक बात यह है कि दिनांकित 31.05.2017 संचार की सराहना की जाए। वह इस प्रकार हैः

" सेवा मे,

प्राचार्य/डीन,

आई. क्यू. सिटी मेडिकल कॉलेज,

सावपुर, बिजरारोड, जेमुआ, दुर्गापुर,

पश्चिम बंगाल-713206

विषयः आई. क्यू. सिटी मेडिकल कॉलेज, बर्दवान, पश्चिम में 150 छात्रों के पांचवें बैच के लिए एमबीबीएस पाठ्यक्रम की अनुमति का नवीनीकरण आई. एम. सी. अधिनियम की धारा 10 ए के तहत शैक्षणिक सत्र के लिए बंगाल, 1956 - रेग.

संदर्भ संख्या 12012/127/2016-एम. ई. आई. (FTS.3084749) दिनांक 31 मई, 2017.

महोदय,

उपरोक्त विषय का संदर्भ देते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कमियों की वर्तमान स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करें और भारतीय चिकित्सा परिषद की सिफारिश जो नहीं की गई थी आपके संस्थान द्वारा अनुपालन किया गया और जिसके लिए केंद्र सरकार आपको एमबीबीएस पाठ्यक्रम में किसी भी छात्र को प्रवेश नहीं देने का निर्देश दिया है शैक्षणिक वर्ष 2017-18

आपको आगे कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है। इस संबंध में तुरंत "।

18. डॉ. आशीष रंजन और अन्य (ऊपर) में, न्यायालय, व्यवहार करते हुए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के साथ, इस प्रकार कहा गया हैः " 2. "मेडिकल कॉलेज विनियमों की स्थापना, 1999" में, "आवेदनों की प्राप्ति के लिए अनुसूची" में नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना और केंद्र द्वारा आवेदनों की प्रक्रिया सरकार और चिकित्सा परिषद भारत "निम्नलिखित को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगाः

आवेदनों की प्राप्ति के लिए समय अनुसूची नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना / परमिशन और प्रक्रिया का नवीनीकरण केंद्रीय सरकार द्वारा आवेदन और भारत की चिकित्सा परिषद

क्रमांक नं.	प्रक्रिया का चरण	अंतिम तिथि
1	आवेदनों की रसीदें केंद्र द्वारा सरकार	15 जून से 7 जून के बीच जुलाई (दोनों दिन सम्मिलित) किसी भी वर्ष का
2	अग्रेषित अनुप्रयोग केंद्र द्वारा सरकार के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया	15 जुलाई तक

3	तकनीकी जांच,मूल्यांकन और के लिए सिफारिशेंद्वारा अनुमति पत्र चिकित्सा परिषद भारत	15 दिसंबर तक
4	जवाब की प्राप्ति / से सिफारिश की केंद्र द्वारा आवेदकसरकार और उसके लिए यदि कोई हो, और आगे बढ़ाना द्वारा अनुपालन केंद्र सरकार ने चिकित्सा परिषद भारत	प्राप्ति के दो महीने बाद से अनुपालन एमसीआई लेकिन 31 तारीख से आगे नहीं जनवरी
5	अंतिम सिफारिशें द्वारा अनुमति मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया	30 अप्रैल तक
6	केंद्र सरकारका पत्र जारी करना द्वारा अनुमति	31 मई तक का

नोट 1. - अनुमति के नवीनीकरण के मामले में, आवेदक 15 तारीख तक भारतीय चिकित्सा परिषद को आवेदन प्रस्तुत करेगा 15 जुलाई "।

19. मनोहर लाल शर्मा बनाम। भारतीय चिकित्सा परिषद और धारा 2, यह आयोजित किया गया हैः

" 19. रिपोर्ट, नियमित और अनुपालन के आधार पर एमसीआई है चिकित्सा महाविद्यालय के उचित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों, उपकरणों, आवास, प्रशिक्षण और अन्य सुविधाओं के संबंध में आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए महाविद्यालय की क्षमता के संबंध में राय बनाने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। प्रवेश क्षमता "।

20. इसके बाद, न्यायालय ने अधिनियम की धारा 10-ए का उल्लेख किया और मेडिकल कॉलेज विनियम, 1999 की स्थापना अधीन आ शासित अछिः

" 24. इस मामले में आकस्मिक निरीक्षण यह पता लगाने के लिए किया गया था कि क्या अनुपालन रिपोर्ट को स्वीकार किया जा सकता है और यह पता लगाने के लिए कि क्या नियमित निरीक्षण में बताई गई कमियां थीं। ठीक किया या नहीं। कमियों को इंगित करके, एमसीआई एक दे रहा है महाविद्यालय को निरीक्षण दल द्वारा देखी गई कमियों को सुधारने का अवसर। यह महाविद्यालय का कर्तव्य है कि वह कमियों को सुधारने के बाद अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करे। एमसीआई कर सकता है यह पता लगाने के लिए कि क्या कमियों को ठीक किया गया था और अनुपालन रिपोर्ट को स्वीकार किया जाए या नहीं, एक आकस्मिक निरीक्षण करें।

आखिरकार, अदालत ने फैसला सुनाया किः

" 27. हमारा यह भी विचार है कि इस तरह के आदेश को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन से दूषित नहीं किया जाता है, विशेष रूप से, जब निरीक्षण दल का गठन करने वाले दो डॉक्टरों के खिलाफ पक्षपात या दुर्भावना का कोई आरोप नहीं लगाया गया है, जिन्होंने 6-7-2013 पर औचक निरीक्षण किया था। जब निरीक्षण दल में निर्विवाद सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा के दो डॉक्टर होते हैं, जो इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, ऐसे निरीक्षण की रिपोर्ट को त्यागने का कोई कारण नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में, हमारा विचार है कि एमसीआई ने मंजूरी को अस्वीकार करते हुए आदेश पारित किया है शैक्षणिक

वर्ष 2013-2014 के लिए दिए गए 150 एमबीबीएस छात्रों के तीसरे बैच के लिए अनुमति के नवीनीकरण के लिए।

21. भारतीय चिकित्सा परिषद बनाम। कलिंग आयुर्विज्ञान संस्थान विज्ञान (के. आई. एम. एस.) और अन्य 3, न्यायालय ने उसमें उत्तरदाताओं के रुख को खारिज कर दिया। यह देखा गयाः

" 24. चिकित्सा शिक्षा को बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए और कब एक विशेषज्ञ निकाय प्रमाणित करता है कि एक मेडिकल कॉलेज में सुविधाएं हैं अपर्याप्त, अदालतें एक अलग दृष्टिकोण लेने के लिए सुसज्जित नहीं हैं बहुत ठोस क्षेत्राधिकार कारणों को छोड़कर मामला जैसे कि निरीक्षण दल की दुर्भावना, इसमें प्रत्यक्ष रूप से विकृति निरीक्षण रिपोर्ट, एमसीआई की ओर से अधिकार क्षेत्र की त्रुटि, आदि। के तहत उच्च न्यायालय को किसी भी परिस्थिति में रिपोर्ट की जांच नहीं करनी चाहिए अपीलीय निकाय-- यह केवल उच्च न्यायालय का कार्य नहीं है। वर्तमान मामले में कानून में कोई आधार नहीं बनाया गया था निरीक्षण दल की रिपोर्ट को अलग रखना।

xxxxx

26. हमें ऐसा लगता है कि एमसीआई और केंद्र सरकार दोनों प्रत्येक ने दो बार प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्ट पर विचार किया है तटस्थ चिकित्सा प्रोफेसर, केंद्र सरकार के साथ दूसरे अवसर पर केआईएमएस को व्यक्तिगत सुनवाई दी गई (और शायद पहले अवसर पर भी) मामला होना चाहिए था उच्च न्यायालय द्वारा कम से कम अकादमिक के लिए एक मौन दिया गया था वर्ष 2015-2016 "

22. यह ध्यान दिया जाए कि उक्त मामले में दोनों न्यायाधीशों की पीठ ने संज्ञान लिया निर्धारकों की स्थिति के बारे में और उस टिप्पणी को प्रतिध्वनित किया जो मनोहर लाल शर्मा (ऊपर) में सुनाई गई थी जिसे हम दोहराना उचित समझते हैं.

हमारा ध्यान मनोहर लाल शर्मा बनाम मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (सुप्रा) मामले में इस अदालत के फैसले की ओर भी आकर्षित किया गया था। जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि चूंकि निरीक्षण डॉक्टरों द्वारा किया जाता है निर्विवाद सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा के, जो विशेषज्ञ हैं इस क्षेत्र में, इस तरह के निरीक्षण की रिपोर्ट को त्यागने का कोई कारण नहीं है "। वर्तमान अपील में, केआईएमएस द्वारा कोई आरोप नहीं लगाया गया है निरीक्षण दल की दुर्भावना या निरीक्षण में कोई विकृति रिपोर्ट दें और इसलिए, निष्कर्षों को चुनौती देने का कोई सवाल ही नहीं है अपने मूल्यांकन में एक तटस्थ, यादृच्छिक रूप से चयनित निरीक्षण दल का।

23. हाथ में मामले में, श्री रोहतगी द्वारा क्या आग्रह किया गया है, सीखा याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील का कहना है कि मूल्यांकनकर्ता रिमांड के आदेश से आगे निकल गए हैं और केवल वही निरीक्षण करते हैं आर. एस. ई. और इस प्रकार असुरक्षित। इस मोड़ पर, ऐसा प्रतीत होता है कि यह मूल्यांकनकर्ताओं के चिह्नों का उल्लेख करता है जो निम्नलिखित पहलुओं से संबंधित हैं (2016) 11 एससीसी 530

" ए) संकाय की कमी 15.90% है जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है।

बी.) निवासियों की कमी 25.88% है जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है।

सी) निरीक्षण के दिन दिखाई गई संख्या मेल नहीं खा रही है संख्या वास्तव में अस्पताल में मौजूद है। यादृच्छिक सत्यापन पर 3, आई.

डी. 1 बजे ओ. पी. डी. पंजीकरण काउंटर पर केवल 110 (40,30 और 40 नए मरीज) हैं। वार्ड में कई मरीज भर्ती हैं। खाँसी, सर्दी, खुजली और केस शीट जैसी छोटी शिकायतें हैं कंप्यूटर और इंटरनेट के साथ कमरा, मनोरंजन कक्ष उपलब्ध नहीं हैं।

डी छात्र छात्रावास:लड़कों के हॉस्टल में आगंतुक कक्ष में ए.सी., कंप्यूटर और इंटरनेट के साथ अध्ययन कक्ष, प्रतिक्रिया कक्ष उपलब्ध नहीं हैं

ई. शरीर रचना विज्ञान विभाग में, कुछ नमूनों को स्थापित नहीं किया जाता है लेकिन बाल्टियों में रखा गया। "

24. इसने कुछ अन्य कमियों को भी पाया है जिनके संबंध में अत्यधिक उपस्थिति, संचालन कार्य, आदि। महाविद्यालय ने जवाब दिया है कि जो इस प्रकार हैः

" उपरोक्त विषय के संबंध में मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा आपके दयालु विचार के लिए निम्नलिखित अनुच्छेद।

1. कि 3 और 4 नवंबर को आयोजित पिछले एमसीआई निरीक्षण के दौरान 2016 हमारे संकाय और निवासियों की कमी 2.18 और 3.38 थी। क्रमशः। हालाँकि 21.03.2017 आकस्मिक निरीक्षण पर और अपनी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता के कारण वे II AM तक नहीं आ सके और मूल्यांकनकर्ताओं के सामने उपस्थित नहीं हो सके।

2. दूसरा, राज्य एन. ई. ई. टी. स्नातकोत्तर परामर्श और डिप्लोमैट इन नेशनल बोर्ड (डी. एन. बी.) परामर्श प्रक्रिया में, कई वरिष्ठ और कनिष्ठ निवासियों और कुछ संकाय सदस्य अपनी परामर्श

के लिए कोलकाता गए थे, इसलिए वे 21.03.2017 पर किए गए निरीक्षण में उपस्थित नहीं हो पाए।

3. तीसरा, इनमें से अधिकांश संकाय और निवासी लंबे समय से हमारे साथ काम कर रहे हैं और इसके लिए दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत किए जा सकते हैं, लेकिन परामर्श के कारण वे असमर्थ थे। इसे बनाने के लिए।

4. यहाँ यह उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि हमारे संकाय और निवासी उपनगरीय क्षेत्रों में चिकित्सा शिविरों में भाग लेने गए थे। ताकि वे मूल्यांकनकर्ताओं के सामने पेश होने के लिए सुबह 11 बजे तक नहीं पहुंच सकें।

इसलिए उनकी अनुपस्थिति को संकाय की भरपाई के लिए माना जा सकता है। और निवासी की कमी "।

25. जैसा कि तथ्यों को उजागर किया गया है, इसमें कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्तामहाविद्यालय ने 150 उम्मीदवारों के प्रवेश के लिए 2017-18 के लिए एक योजना प्रस्तुत की थी।इस बात पर भी कोई विवाद नहीं है कि एक निरीक्षण और सुनवाई हुई थीसमिति ने कुछ सिफारिशें की थीं और केंद्रीयसरकार ने अनुपालन सत्यापन रिपोर्ट के लिए इसे एमसीआई को वापस भेजना उचित समझा। अधिनियम की धारा 10-ए से संबंधित है - एम. सी. आई. द्वारा केंद्र सरकार को अपनी सिफारिश करते समय या तो अनुमोदन करते हुए या अस्वीकार करते हुए लिया जाना। उप-धारा (7) इस प्रकार है निम्नलिखित हैः

" 10-ए. नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए अनुमति, अध्ययन का नया पाठ्यक्रम, आदि (1)-(6) (7) परिषद, खंड के तहत अपनी सिफारिशें करते हुए (बी) उप-धारा (3) और केंद्र सरकार, पारित करते समय उप-धारा (4) के तहत योजना को मंजूरी या अस्वीकृत करने वाले आदेश में निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखा जाएगाः अर्थात्

(क) क्या प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज या मौजूदा मेडिकल कॉलेज जो अध्ययन या प्रशिक्षण का नया या उच्चतर पाठ्यक्रम शुरू करना चाहता है,
धारा 19ए के तहत परिषद द्वारा निर्धारित चिकित्सा शिक्षा के न्यूनतम मानकों की पेशकश करने की स्थिति में होगा या, जैसा भी मामला हो, स्नातकोत्तर के मामले में धारा 20 के तहत चिकित्सा शिक्षा।

(ख) क्या वह व्यक्ति जो एक मेडिकल कॉलेज या मौजूदा मेडिकल कॉलेज स्थापित करना चाहता है, जो अध्ययन या प्रशिक्षण का एक नया या उच्चतर पाठ्यक्रम शुरू करना चाहता है या इसकी प्रवेश क्षमता को बढ़ाना चाहता है,पर्याप्त वित्तीय संसाधन;

(ग) क्या उचित सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों, उपकरणों, आवास, प्रशिक्षण और अन्य सुविधाओं के संबंध में आवश्यक सुविधाएं हैं।मेडिकल कॉलेज का संचालन या नया पाठ्यक्रम संचालित करना या अध्ययन या प्रशिक्षण या बढ़े हुए प्रवेश को समायोजित करना क्षमता प्रदान की गई है या इसके भीतर प्रदान की जाएगी योजना में निर्दिष्ट समय-सीमा;

(घ) अस्पताल में पर्याप्त सुविधाएं हैं या नहीं। इस तरह के मेडिकल कॉलेज या अध्ययन या प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम में भाग लेने की संभावना वाले छात्रों की संख्या या बढ़ी हुई प्रवेश क्षमता के परिणामस्वरूप, प्रदान किया गया है या प्रदान किया जाएगा योजना में निर्दिष्ट समय-सीमा;

(ई) क्या इस तरह के चिकित्सा में भाग लेने की संभावना वाले छात्रों को उचित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कोई व्यवस्था या कार्यक्रम तैयार किया गया हैः कॉलेज या अध्ययन या प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम रखने वाले व्यक्तियों द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यताएँ;

(च) अभ्यास के क्षेत्र में श्रमशक्ति की आवश्यकता दवा; और

(छ) कोई अन्य कारक जो निर्धारित किए जाएं।

26. मनोहर लाल शर्मा (उपरोक्त) मामले में, न्यायालय ने चिकित्सा परिषद (संशोधन) अधिनियम, 2010 का उल्लेख किया है जो धारा 3-बी (बी) के अनुसार बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को शक्तियां प्रदान करता है। उक्त प्रावधान एस इस प्रकारः

" 3 - बी. अधिनियम के कुछ संशोधन। - उस अवधि के दौरान जब परिषद को हटा दिया गया है

(ख) निदेशक मंडल -

(i) परिषद की शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का निर्वहन करना। इस अधिनियम के तहत और इस उद्देश्य के लिए, इस अधिनियम के प्रावधान इस संशोधन के अधीन प्रभावी होंगे कि परिषद के संदर्भों को बोर्ड के संदर्भों के रूप में समझा जाएगा राज्यपाल;

(ii) नए भवनों की स्थापना के लिए स्वतंत्र रूप से अनुमति प्रदान करना। मेडिकल कॉलेज या अध्ययन या प्रशिक्षण का एक नया या उच्चतर पाठ्यक्रम खोलना या अध्ययन के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना। या धारा 10ए में निर्दिष्ट प्रशिक्षण या संबंधित व्यक्ति या कॉलेज को केंद्र की पूर्व अनुमति के बिना धारा 10ए के तहत प्रदान की गई सुनवाई का उचित अवसर देना। उस धारा के तहत सरकार, जिसमें शक्ति का प्रयोग भी शामिल है अंततः उसी को अनुमोदित या अस्वीकृत करनाः और

(iii) केंद्र सरकार के पास लंबित मामलों का निपटारा करना। धारा 10ए के तहत उसी की प्राप्ति पर।

27. धारा 3-बी (बी) की व्याख्या करते हुए न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित कियाः

" 22. एम. सी. आई., केंद्र सरकार द्वारा पूर्व मंजूरी के साथ। धारा 10-ए और 33 द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 ने नियमों को मेडिकल कॉलेज विनियमों की स्थापना के रूप में जाना। 1999 के विनियमों का विनियम 8 नए महाविद्यालय की स्थापना के लिए अनुमति देने से संबंधित है। आवेदन/योजना प्रस्तुत की गई आवेदकों द्वारा मूल्यांकन किया जाता है और एमसीआई के निरीक्षकों की टीम द्वारा भौतिक निरीक्षण करके सत्यापन किया जाता है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस पाठ्यक्रम के पहले वर्ष में प्रवेश के लिए आवेदक को एल ओ पी दे सकता है। और कॉलेज द्वारा

न्यूनतम मानक में उल्लिखित वार्षिक लक्ष्य को प्राप्त करने के अधीन हर साल अनुमति का नवीनीकरण किया जाता है। प्रतिवर्ष 150 प्रवेशों के लिए मेडिकल कॉलेज की आवश्यकताएँ विनियम, 1999 "। उपर्युक्त विनियम की अनुसूची I मेडिकल कॉलेज और उसके शिक्षण में आवास की व्यवस्था करता है अस्पताल। अनुसूची II कॉलेज और अस्पताल में विभिन्न विभागों के लिए आवश्यक उपकरणों से संबंधित है। आवश्यकताएँ वैधानिक रूप से निर्धारित की गई हैं और इसलिए, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने में उल्लिखित वैधानिक आवश्यकताओं को कम करने की कोई शक्ति नहीं उपर्युक्त विनियम "।

28. इस स्तर पर, हम उपयोगी रूप से गणना किए गए निर्देशों का उल्लेख कर सकते हैं रॉयल मेडिकल ट्रस्ट (पंजीकृत) में और एक अन्य वी। भारत संघ और एक अन्य, जिसमें तीन-न्यायाधीशों की पीठ न्यायसंगतता पर विचार कर रही थी केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए संचारों में मेडिकल कॉलेजों के संबंध में पसंदीदा आवेदनों को अस्वीकार करने की सिफारिश की गई है। शैक्षणिक वर्ष 2014-15 के लिए आवेदक। न्यायालय ने अधिनियम की धारा 10-ए और एमसीआई द्वारा बनाए गए विनियमों का उल्लेख करते हुए और विभिन्न पहलुओं पर आगे बढ़ते हुए, फैसला सुनाया गयाः

" 31. एमसीआई और केंद्र सरकार को धारा 10 ए और विनियमों के तहत निगरानी की शक्तियां दी गई हैं। इन अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कार्यों का अच्छी तरह से निर्वहन करें। वैधानिक सीमाओं के साथ-साथ विनियमों की अनुसूची के अनुरूप है। यदि उनकी ओर से निष्क्रियता है या नहीं समय-सारणी का पालन करने पर सभी संबंधितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना तय है। भारत संघ की ओर से दायर हलफनामे से पता चलता है कि हालांकि सीटों की

संख्या में वृद्धि हुई थी, जाहिर है कि नए कॉलेजों की स्थापना के लिए दी गई अनुमतियों के कारण, नवीनीकरण मामलों की अस्वीकृति के कारण परिणामी प्रभाव शैक्षणिक वर्ष के लिए उपलब्ध सीटों की संख्या के मामले में शुद्ध नुकसान था। इस प्रकार इसने न केवल छात्र समुदाय के लिए अवसर खो दिया, बल्कि साथ ही डॉक्टरों की कम संख्या उपलब्ध होने के मामले में समाज को भी नुकसान पहुंचाया। इसलिए एमसीआई और केंद्र सरकार को उचित परिश्रम करना चाहिए। जिस दिन आवेदन प्राप्त होते हैं। विभिन्न चरणों और समय-सीमाओं को दर्शाने वाली अनुसूची में हर संभव व्यवस्था होनी चाहिए। संभाव्यता और एक ही समय में इसका पालन करना चाहिए विभिन्न स्तरों पर प्राकृतिक न्याय के पालन की आवश्यकताएँ। हमारे विचार में अनुसूची को आदर्श रूप से निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिएः

(2015) 10 एस. सी. सी. 19

(ए) पहले स्तर पर आवेदन का प्रारंभिक मूल्यांकन होना चाहिए इसमें आवश्यक आवश्यकताओं की जाँच करना शामिल है जैसे कि अनिवार्यता प्रमाण पत्र, संबद्धता के लिए सहमति और भूमि जैसी भौतिक विशेषताएं। और अस्पताल की आवश्यकता। यदि कोई आवेदक इन्हें पूरा करने में विफल रहता है

(ख) निरीक्षण तब एम. सी. आई. के निरीक्षकों द्वारा किया जाना चाहिए। बहुत स्वभाव से इस तरह के निरीक्षण में एक तत्व होना चाहिए आश्चर्य होता है। इसलिए एमसीआई को किसी भी समय

निरीक्षण करने के लिए लगभग तीन से चार महीने का पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। निरीक्षण आम तौर पर जनवरी तक किया जाना चाहिए। आकस्मिक निरीक्षण से यह सुनिश्चित होगा कि आवश्यक सुविधाएं और बुनियादी ढांचा हमेशा अपने स्थान पर रहे और न ही इसे उधार लिया जाए और न ही रखा जाए। अस्थायी रूप से।

(ग) निरीक्षण के परिणाम या परिणाम की सूचना फिर संवाद करें। यदि आधारभूत संरचना और सुविधाएं व्यवस्थित हैं, तो संबंधित मेडिकल कॉलेज को आवश्यक अनुमति/नवीनीकरण दिया जाना चाहिए। हालाँकि, यदि कोई कमियाँ हैं या कमियों को इंगित करने के बाद, एमसीआई को अनुपालन की रिपोर्ट करने के लिए संबंधित कॉलेज को पर्याप्त समय देना चाहिए।

(डी) यदि अनुपालन की सूचना दी जाती है और आवेदक कहता है कि कमियां दूर हो गई हैं, एमसीआई को अनुपालन करना चाहिए सत्यापन। यह संभव है कि इस तरह के अनुपालन को वास्तविक भौतिक सत्यापन के बिना भी स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन यह मूल्यांकन पूरी तरह से एमसीआई और केंद्र सरकार के विवेक पर छोड़ दिया गया। ऐसे मामलों में जहां वास्तविक भौतिक सत्यापन की आवश्यकता होती है, एमसीआई और केंद्र सरकार को आयोग से पहले इस तरह के सत्यापन का कारण बनना चाहिए। -समय सीमा।

(ई) इस तरह के सत्यापन का परिणाम यदि संबंधित मेडिकल कॉलेज के पक्ष में सकारात्मक है, तो आवेदक को आवश्यक अनुमति/नवीनीकरण दिया जाना चाहिए। लेकिन अगर कमियां अभी

भी बनी रहती हैं या उन्हें हटाया नहीं गया है, तो आवेदक अब तक इस अधिकार से वंचित रहेगा।शैक्षणिक वर्ष का संबंध है। [जोर दिया गया]

29. अधिनियम की धारा 10-ए को पढ़ने पर, नियम और विनियम, जैसा कि मनोहर लाल शर्मा (ऊपर) में संदर्भित किया गया है, और रॉयल मेडिकल ट्रस्ट (ऊपर) में व्यक्त विचार, यह होगा एमसीआई की शक्ति को सीमित करने के लिए एक पूर्ण सिद्धांत के रूप में निर्धारित करना अनुचित है कि एक बार केंद्र सरकार मामले को वापस भेज देती है अनुपालन सत्यापन के लिए एमसीआई और मूल्यांकनकर्ता कॉलेज का दौरा करते हैं वे केवल उल्लिखित वस्तुओं का सत्यापन करेंगे और कुछ अन्य कमियों को महसूस करने पर भी नेल्सन की नज़र डालेंगे। यह प्लेइंग पॉसम होगा। अनुपालन सत्यापन के लिए केंद्र सरकार का निर्देश रिपोर्ट को सीमित रिमांड के रूप में नहीं माना जाना चाहिए जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता या किसी अन्य कानून के ढांचे के भीतर समझा जाता है। खुली रिमांड और सीमित रिमांड के सिद्धांतों के बीच अंतर, हम सोचने के लिए तैयार हैं, आकर्षित नहीं हैं। चाहे यह स्पष्ट रूप से कहा गया हो, उक्त सिद्धांत रॉयल मेडिकल ट्रस्ट में प्राधिकरण से भी नहीं आता है। (ऊपर)। इस संदर्भ में, सुनवाई समिति की निष्पक्षता और केंद्र सरकार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। असली। अनुपालन करने वाली संस्थाओं को हमेशा डेमोक्लिस की तलवार के नीचे नहीं रखा जाना चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा निभाई गई सकारात्मक भूमिका से स्थिरता लाई जा सकती है। और स्थिरता और निष्पक्षता बोधगम्य होगी। यदि विचार व्यक्त करते

समय कारणों का उल्लेख किया जाता है और कारणों की अनुपस्थिति निर्णय को संवेदनशील रूप से अतिसंवेदनशील बनाती है।

30. यह कहने के बाद, हम मामले को बंद करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। याचिकाकर्ता 2013-14 के बाद से कॉलेज चला रहे हैं। हम रहे हैं। जानकारी दी गई कि जो छात्र अपनी शिक्षा जारी रख रहे हैं, वे 2017-18 के लिए जारी रखेंगे। जैसा कि हम पाते हैं कि केंद्र सरकार का आदेश है कोई तर्क नहीं। अपनी ओर से कारण बताना अनिवार्य है। उक्त उद्देश्य के लिए, हम चाहेंगे कि केंद्र सरकार याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का और अवसर प्रदान करे और उनकी सहायता भी ले। संविधान पीठ द्वारा 2017 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 408, जिसका शीर्षक अम्मा चंद्रावती एजुकेशनल एंड चैरिटेबल है, में पारित 18 जुलाई, 2017 के आदेश के अनुसार नवगठित निगरानी समिति ट्रस्ट और अन्य v. भारत संघ और दूसरा और उसके बाद दो सप्ताह के भीतर निर्णय लेते हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि निर्णय में कारण शामिल होंगे। हम दोहराते हैं कि निर्णय एक होना चाहिए एक को सूचित किया।

31. वर्तमान के लिए मामले से अलग होने से पहले, यह कहना उचित है कि "स्वास्थ्य", एक छह अक्षर का शब्द, जब उपयुक्त रूप से लिखा जाता है और स्पष्ट रूप से, शरीर और मन को समग्र बनाता है और एक व्यक्ति विजयी महसूस करता है। आदत और प्रकृति के अलावा, कुछ बाहरी सहायता की आवश्यकता है। और इसलिए, यह आवश्यक है कि ऐसे संस्थान हों जो चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के योग्य हों ताकि समाज में न केवल योग्य डॉक्टर हों बल्कि त्रुटिहीन और संवेदनशील गुणों वाले डॉक्टर भी हों। एक चूक है आपदा को आमंत्रित करने की क्षमता। बिना किसी काम के नहीं, हिप्पोक्रेट्स ने कहा था, " एक बुद्धिमान व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि स्वास्थ्य उसकी सबसे मूल्यवान संपत्ति है। इसलिए, उन अनुपालन संस्थानों पर जोर दिया जा रहा है जो वास्तव में ऐसा कर सकते हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करके

डॉक्टरों को शिक्षित करें ताकि उनके पास उत्कृष्टता के अंतर्निहित और विकसित गुण हों।

32. 24 अगस्त, 2017 को मामले को सूचीबद्ध करें और निर्णय की प्रतीक्षा करें। केंद्र सरकार।

कल्पना के. त्रिपाठी

निर्देश जारी किए गए।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल **'सुवास'** की सहायता से अनुवादक द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।